

सवाल जवाब

कनेक्टिविटी, नीति, कारोबारी सुगमता के बल पर निवेश खींच रहा पूर्वांचल

रणनीतिक स्थिति, कुशल कार्यबल, मजबूत कृषि आधार और तेजी से सुधरती कनेक्टिविटी का लाभ उठाकर उत्तर प्रदेश सरकार पूर्वी उत्तर प्रदेश को उद्योग और निवेश का प्रमुख केंद्र बना रही है। प्रदेश में अपर मुख्य सचिव (औद्योगिक विकास) और आईआईटीसी दीपक कुमार ने सिद्धार्थ कलहंस को बताया कि किस तरह इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और संतुलित क्षेत्रीय विकास होगा। मुख्य अंशः

पूर्वी उत्तर प्रदेश विशेषकर वाराणसी को काफी निवेश प्रस्ताव मिल रहे हैं। सरकार इस क्षेत्र में जमीन कैसे उपलब्ध कराएगी ?

उत्तर प्रदेश में जमीन बाधा नहीं है बल्कि दूसरों से होड़ में आने निकलने का मौका है। राज्य ने जीआईएस के जरिये 75,000 एकड़ से अधिक औद्योगिक लैंड बैंक तैयार किया है, जिससे निवेशक बुनियादी ढांचे, यूटिलिटीज और कनेक्टिविटी की पूरी जानकारी के साथ निवेश के लिए तैयार स्थल देख सकते हैं। एक्सप्रेसवे के बड़े नेटवर्क का फायदा उठाने के लिए प्रदेश प्रमुख एक्सप्रेसवे और आर्थिक गलियारों के किनारे 27 एकीकृत विनिर्माण एवं लॉजिस्टिक्स क्लस्टर तैयार कर रहा है। पूर्वांचल में अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, गोरखपुर, आजमगढ़ और अंबेडकर नगर में ये क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे और मल्टीमोडल कनेक्टिविटी के साथ ‘प्लग एंड प्ले’ औद्योगिक तंत्र तैयार हो रहा है।

प्रदेश सरकार पूर्वी उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा देना चाहती है ?

हम भविष्य पर नजर रखते हुए इस क्षेत्र की मौजूदा ताकत को और बढ़ा रहे हैं। निवेश आकर्षित करने, रोजगार उत्पन्न करने और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश अपनी रणनीतिक स्थिति, कुशल कार्यबल, मजबूत कृषि आधार तथा तेजी से बढ़ती कनेक्टिविटी का उपयोग कर पूर्वी उत्तर प्रदेश को प्रमुख औद्योगिक और

निवेश केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है। खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित उद्योग, वस्त्र और परिधान (बनारसी सिल्क तथा भदोही कालीन क्लस्टर), पर्यटन, आतिथ्य, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स तथा वेयरहाउसिंग, आईटी एवं आईटीईएस, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी), डेटा सेंटर और डिजिटल ढांचा जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है। इन क्षेत्रों में निवेश सुगम बनाने के लिए व्यापक नीतिगत तंत्र बना है, जिसमें 40 से अधिक क्षेत्रों की नीतियां तथा प्रोत्साहन योजनाएं हैं।

निवेशकों को पूर्वांचल निवेश के अनुकूल क्यों लग रहा है ?

बुनियादी ढांचे से भरोसा आता है और भरोसा निवेश लाता है, जिससे रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व बदलाव से गुजरा पूर्वांचल विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, नीतिगत सहयोग और कारोबारी सुगमता बढ़ने के कारण भारत के सबसे आकर्षक निवेश स्थलों में जगह बना रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और तैयार हो रहे गंगा एक्सप्रेसवे समेत बढ़ी हुई एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी निवेशकों का भरोसा बढ़ाती है। इसके अलावा राष्ट्रीय जलमार्ग-1 और वाराणसी में मल्टीमोडल टर्मिनल देश के भीतर माल की आवाजाही को किफायती बनाते हैं और सीधे पूर्वी बंदरगाहों तक पहुंचाते हैं। पूर्वी समर्पित माल गलियारा तथा व्यापक रेलवे नेटवर्क के कारण कनेक्टिविटी बढ़ने से भी माल ढुलाई की लागत घटी है और बाजार तक पहुंच बढ़ी है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में आईटी उद्योगों खास तौर पर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) तथा डेटा सेंटरों के लिए क्या संभावनाएं हैं ?

प्रतिभा हर जगह मौजूद है तो अवसर भी हर जगह होने चाहिए। आगे प्रौद्योगिकी में निवेश महानगरों तक ही सीमित नहीं रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी और ज्ञान सेवाओं का अहम ठिकाना बन रहा है, जिसे जीसीसी नीति 2024, आईटी एवं आईटीईएस नीति 2022 तथा डेटा सेंटर नीति से मदद मिल रही है। पूर्वांचल आईआईटी-बीएचयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तथा अन्य प्रमुख संस्थानों से आ रही प्रतिभा, कम परिचालन लागत, बढ़ती मल्टीमोडल कनेक्टिविटी तथा निवेश के लिए तैयार



औद्योगिक बुनियादी ढांचे के बल पर दूसरे क्षेत्रों से होड़ में आगे रहता है। यह ताकत उत्तर प्रदेश के ‘हब एंड स्पोक’ जीसीसी मॉडल के अनुकूल है, जिससे कंपनियां लागत काबू में रखते हुए बेहतरीन प्रतिभा तक पहुंच सकती हैं। प्रयागराज, उन्नाव, झांसी और बुंदेलखंड में आईटी, आईटीईएस तथा डेटा सेंटरों में बढ़ता निवेश बताता है कि प्रदेश का प्रौद्योगिकी तंत्र एनसीआर से आगे बढ़ रहा है।

अगली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की कैसी तैयारी है और पूर्वी उत्तर प्रदेश से कितनी परियोजनाएं शुरू होने की उम्मीद है ?

निवेशकों के बढ़ते भरोसे के कारण पिछले साल ही उत्तर प्रदेश में 4,860 नए कारखाने खुले हैं, जिससे पंजीकृत कारखानों की संख्या 32,332 तक पहुंच गई है। हमारी कामयाबी का अंदाजा यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 और चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की सफलता से लगता है। इस समिट में 33.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए और चौथी सेरेमनी में 10 लाख रुपये से अधिक की 14,701 परियोजनाएं शुरू हुईं। अगली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की घोषणा मुख्यमंत्री सही समय पर करेंगे। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रहने की उम्मीद है, जहां वाराणसी,

प्रयागराज, गोरखपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, बाराबंकी और अंबेडकरनगर जैसे जिलों में खाद्य प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स, कपड़ा, पर्यटन, रक्षा विनिर्माण एवं औद्योगिक बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

पर्यावरण संरक्षण के साथ संभव है ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था

उद्योग और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ चलें तो उत्तर प्रदेश के लिए ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करना संभव है। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है कि पर्यावरण संरक्षण के साथ औद्योगिक विकास भी होता रहे। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) के चेयरमैन डॉ आरपी सिंह ने सिद्धार्थ कलहंस को बताया कि यह कैसे संभव हो रहा है। प्रमुख अंशः

पूर्वी उत्तर प्रदेश खासकर वाराणसी में किस तरह के उद्योगों को बढ़ावा मिलना चाहिए, जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो ?

पूर्वी उत्तर प्रदेश में सभी उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता है। अब उद्योगों से निकलने वाले खराब जल को सही करने वाली तकनीकें हैं और वायु प्रदूषण पर काबू पाने वाले उपकरण भी हैं। उत्तर प्रदेश का इस हिस्से में प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, उपजाऊ मिट्टी और खूब पानी है, इसलिए कृषि पर आधारित उद्योगों के लिए भी यह बहुत उपयुक्त है।

क्या यहां के पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में उद्योग और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ चल सकते हैं ?

बिल्कुल। उद्योग और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ चल सकते हैं। शर्त यही है कि उद्योग अपने यहां से निकलने वाले प्रदूषणकारी पदार्थों के उपचार के लिए सही तकनीक चुनें और इस्तेमाल करें।

सभी आवश्यक संसाधन होने पर भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी है। क्या सौर ऊर्जा इस कमी को पूरा कर सकती है ?

यह इलाका उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ताप बिजली बना रहा है। सौर ऊर्जा से बिजली बनाने की तो यहां और भी अधिक संभावनाएं हैं क्योंकि मिर्जापुर, प्रयागराज और अन्य



जिलों में सौर ऊर्जा की क्षमता बहुत अधिक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जैव ईंधन ऊर्जा का एक और स्रोत हो सकता है। चूंकि पूर्वांचल में बेहद समृद्ध कृषि और डेरी क्षेत्र है, इसलिए फसल अवशेषों जैसे पराली और दूसरे संसाधनों का इस्तेमाल कर जैव ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है।

उद्योगों में तेज वृद्धि के साथ पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए यूपीपीसीबी क्या सावधानी बरत रहा है ?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसे पाने के लिए औद्योगिक विकास का पर्यावरण संरक्षण के साथ तालमेल होना बेहद जरूरी है। इसके लिए यूपीपीसीबी उत्पादन के आखिरी चरण में प्रदूषण रोकने के पारंपरिक उपायों पर जोर देने के साथ उद्योगों को स्वच्छ

उत्पादन तकनीकें, संसाधनों का सबसे अच्छा इस्तेमाल करने वाली प्रक्रियाएं, जल संरक्षण के उपाय और कचरा कम करने के तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है ताकि हम आर्थिक वृद्धि के साथ नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य भी प्राप्त कर सकें।

पर्यावरण पर पैनी नजर रखने के लिए बोर्ड एआई से काम करने वाला अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष और डेटा सेंटर बना रहा है। पहले चरण में इससे पूरे प्रदेश में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और बायोमेडिकल कचरा उपचार व निपटान सुविधाओं पर तत्काल नजर रखी जा सकेगी। इससे नियमों का ज्यादा पालन होगा और समय पर नियामक कार्रवाई होगी।

यूपीपीसीबी प्रदेश में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने और प्रदूषण कम करने के लिए क्या कर रहा है ?

जन भागीदारी के बगैर पर्यावरण संरक्षण कारगर नहीं हो सकता। यूपीपीसीबी नागरिकों, शिक्षण संस्थानों, उद्योगों और स्थानीय लोगों को पर्यावरण का ध्यान रखने वाले तरीके अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है। हमारे बोर्ड ने एनएसएस के कार्यक्रमों, स्कूलों और कॉलेजों में अपनी गतिविधियों, पौधरोपण अभियान, प्लास्टिक-मुक्त अभियान और विश्व पर्यावरण दिवस आदि कार्यक्रमों का आयोजन शुरू किया है। युवाओं को जोड़ने के लिए हम अपना मैस्कॉट ‘सारस साथी’ लाए हैं और ‘श्रीन कमांडो प्रोग्राम’, ‘बी अ चेंज मेकर प्रोग्राम’ व ‘एक्सपर्ट लेक्चर सीरीज’ शुरू किए हैं। बोर्ड वायु एवं जल प्रदूषण, कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक कचरा घटाने तथा आम जनता को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली के प्रति जागरूक करने के लिए डिजिटल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है।

बढ़ते उत्तर प्रदेश में बैंकिंग क्षेत्र के लिए हैं असीमित अवसर

वर्ष 2030 तक 1 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का उत्तर प्रदेश का लक्ष्य पूरा करने में बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका होगी बहुत अहम

वीरेंद्र सिंह रावत

तकरीबन 25 करोड़ लोगों को अपनी सीमाओं के भीतर समेटने वाला उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य तो है ही, आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध राज्यों में भी शुमार हो गया है। चालू वित्त वर्ष में इसका सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 40 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। इसलिए कहने की जरूरत नहीं कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश का समग्र विकास बहुत जरूरी है।

इतनी बड़ी आबादी और जीएसडीपी के साथ उत्तर प्रदेश में भारीभरकम बाजार मौजूद है और यहां की व्यापक अर्थव्यवस्था में बैंकिंग के लिए भी असीमित अवसर हैं। आबादी के साथ प्रदेश की भौगोलिक स्थिति भी कुछ ऐसी है कि बैंकों के लिए यहां नई योजनाएं पेश करना, बाजार से मिलने वाले जवाब को समझना और खुदरा तथा संस्थागत ग्राहकों के लिए नई आजमाइश करने का भरपूर मौका मिलता है।

उत्तर प्रदेश में काम कर रहे सभी बैंकों के पास मार्च 2026 के अंत में 21.43 लाख करोड़ रुपये से अधिक कुल जमा राशि थी, जो पिछले साल मार्च की तुलना में 10.7 फीसदी अधिक रही। सरकारी आंकड़ें खंगालें तो मार्च 2026 के अंत में बैंकों द्वारा बांटे गए कुल ऋण का आंकड़ा भी मार्च 2026 के अंत में 12.85 लाख करोड़ रुपये के पार चला गया था, जो उससे एक साल पहले की तुलना में 13.54 फीसदी अधिक रहा।

उत्तर प्रदेश में काम कर रहे सभी सार्वजनिक और निजी बैंकों, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को मिला लें तो पूरे प्रदेश में लगभग 21,000 बैंक



उत्तर प्रदेश में विभिन्न बैंकों की 21,000 से अधिक शाखाएं हैं, जिनके जरिये वे बुनियादी बैंकिंग सेवाएं ही नहीं दे रहे हैं बल्कि उद्यमियों और बुनियादी ढांचे के लिए भरपूर कर्ज भी बांट रहे हैं

शाखाएं हैं। इनमें वाणिज्यिक बैंक आगे हैं, जिनकी 14,200 से अधिक शाखाएं हैं। आरआरबी की करीब 4,300 शाखाएं हैं और सहकारी बैंकों की 1,690 से ज्यादा शाखाएं काम कर रही हैं। इतने बड़े जाल के साथ बैंकिंग वाकई में प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बड़ा स्तंभ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंचाने के लक्ष्य की घोषणा कर दी। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए प्रदेश को सुधारों का अगला चरण लागू करना ही होगा और इसके लिए बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स, परिवहन, पर्यटन, आतिथ्य तथा सेवा जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर

सरकारी और निजी निवेश की दरकार होगी। इस निवेश के लिए ज्यादातर रकम बैंकों से कर्ज के जरिये ही आएगी और यह पूर्वी उत्तर प्रदेश (पूर्वांचल), बुंदेलखंड, मध्य उत्तर प्रदेश (मध्यांचल) तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश (पश्चिमांचल) जैसे अलग-अलग इलाकों में वाणिज्यिक एवं दूसरे बैंकों की मजबूत पैठ तथा नेटवर्क से ही संभव हो सकता है। उत्तर प्रदेश में ऋण और जमा अनुपात (सीडी रेश्यो) 60 फीसदी से ज्यादा हो गया है मगर मुख्यमंत्री ने बैंकों से स्टार्टअप, युवा उद्यमियों तथा सूक्ष्म उद्यमों को ऋण देकर यह अनुपात 70 फीसदी तक पहुंचाने के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे के बढ़ते जाल की बदौलत अब

‘एक्सप्रेसवे प्रदेश’ कहा जाने लगा है। मगर बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पूरी होने में समय लगता है और भारी पूंजी की जरूरत होती है, जो बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान ही मुहैया करा सकते हैं।

भारत में अधिकतर बैंकिंग लेनदेन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के जरिये ही होता है। ग्रामीण और सुदूर इलाकों में सरकारी बैंकों का दखल खास तौर पर बहुत अधिक है। वे प्राथमिक क्षेत्र में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने में आगे हैं, जिनमें बिना किसी शर्त वाला ‘प्रधानमंत्री जन धन योजना’ खाता भी शामिल है। केंद्र सरकार ने घरेलू अर्थव्यवस्था को नकदी से डिजिटल में आसानी से बदलने के लिए वित्तीय समावेशन की महत्वाकांक्षी ‘जन धन योजना’ शुरू की थी। इस समय सबसे अधिक जन धन खाते उत्तर प्रदेश में ही हैं, जो इस योजना के तहत देश भर में खुले कुल खातों के लगभग 15 फीसदी हैं।

जन धन योजना का मकसद हर व्यक्ति को बुनियादी बचत बैंक खाते की सुविधा देनी है। इस योजना ने बड़े पैमाने पर वित्तीय समावेशन, जमा जुटाने और कर्ज आवंटन के मामले में कई वैश्विक स्तर की उपलब्धियां हासिल की हैं।

भारत अपने नागरिकों और प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) द्वारा विदेशी मुद्रा में भेजी गई रकम (रेमिटेंस) पाने वाले शीर्ष देशों में भी शामिल है। रेमिटेंस वह रकम होती है, जो विदेश में काम करने वाले लोग भारत में रह रहे अपने परिवारों की वित्तीय मदद के लिए भेजते हैं। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश की गिनती सबसे ज्यादा विदेशी रेमिटेंस पाने वाले चार राज्यों में होती है। बैंक डिजिटल चैनलों, स्विफ्ट वायर ट्रांसफर आदि के जरिये नागरिकों और एनआरआई को आसानी से पैसे भेजने की सुविधा भी देते हैं।



Uttar Pradesh Pollution Control Board

REFUSE SINGLE USE PLASTIC

PLASTIC CARRY BAG

PLASTIC BOTTLE

PLASTIC CUTLERY

PLASTIC STRAW

ADOPT ECO-FRIENDLY ALTERNATIVES

CLOTH/JUTE BAG

STEEL/GLASS BOTTLE

BAMBOO/WOODEN CUTLERY

REUSABLE STRAW



Sarus Saathi
The Mascot of UPPCB